International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 6.924 Volume 10, Issue 05, May 2023
Website- www.aarf.asia, **Email** : editoraarf@gmail.com

स्वच्छ भारत अभियान : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. सिंह अरुण कुमार लक्ष्मण
असि. प्रोफेसर–समाजशास्त्रा
काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही

शोध सार

स्वच्छता किसी भी सभ्य समाज की पहचान मानी जाती है। यह केवल व्यक्तिगत आदतों या घर–आँगन की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना, सामूहिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक व्यापक विषय है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में स्वच्छता का प्रश्न लंबे समय तक एक गंभीर सामाजिक चुनौती रहा है। खुले में शौच, कचरा प्रबंधन की कमी, गंदे सार्वजनिक स्थल और स्वच्छता के प्रति उदासीनता ने स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक गरिमा पर नकारात्मक प्रभाव डाला। इसी पृष्ठभूमि में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता संबंधी आदर्शों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह अभियान केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन (Social Behavior Change) की एक व्यापक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य केवल शौचालय निर्माण या कचरा निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के मनोविज्ञान, सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक व्यवहारों में परिवर्तन लाना है। इस अध्ययन में स्वच्छ भारत अभियान के सामाजिक आयामों, संरचनात्मक प्रभावों, वर्ग–जाति–लिंग आधारित अंतरों, ग्रामीण–शहरी विभाजन, सामुदायिक सहभागिता तथा दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किया जाएगा।

मुख्य शब्द : स्वच्छ भारत अभियान, गांधीवादी मिशन, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता

स्वच्छता का सामाजिक आख्यान

स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत या सार्वजनिक नीति का विषय नहीं है, बल्कि यह एक गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम रखती है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजघाट पर झाड़ू उठाकर शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan) मात्र एक सरकारी योजना न होकर एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। इस अभियान ने खुले में शौच (Open Defecation) की सदियों पुरानी प्रथा

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) की एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रखा। लेकिन एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो यह अभियान केवल शौचालयों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की संरचना, जातीय मान्यताओं, लैंगिक असमानताओं, आर्थिक विषमताओं और सांस्कृतिक आदतों के एक जटिल जाल से जूझने का प्रयास है।

इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि स्वच्छ भारत अभियान ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार प्रभावित किया, इसके क्रियान्वयन में कौन–सी सामाजिक बाधाएँ आईं, और इसने पारंपरिक मान्यताओं तथा व्यवहारों में किस हद तक परिवर्तन किया। जयपुर के खो नागोरियन क्षेत्र में किए गए गुणात्मक सर्वेक्षण , पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं पर पड़े प्रभाव का अध्ययन , राजस्थान के उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल कानपुर ग्राम पंचायत में किए गए क्षेत्रीय कार्य , और गया की ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में किए गए आईसीएसएसआर परियोजना के निष्कर्ष हमें यह समझने में मदद करेंगे कि यह अभियान किस प्रकार सफल हुआ और कहाँ यह अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान की संरचना और उद्देश्य

स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की एक व्यापक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छता की स्थिति में क्रांतिकारी सुधार लाना और नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना है। इस मिशन की संरचना को दो प्रमुख घटकों ग्रामीण और शहरी में विभाजित किया गया, ताकि दोनों क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुसार योजनाएँ बनाई जा सकें।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का मुख्य लक्ष्य खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना था। लंबे समय तक ग्रामीण भारत में शौचालयों की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण लोग खुले में शौच करने को बाध्य थे, जिससे जलजनित रोगों, कुपोषण और पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएँ उत्पन्न होती थीं। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके साथ ही व्यवहार परिवर्तन पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि केवल शौचालय बनाना पर्याप्त नहीं था, उनका नियमित उपयोग सुनिश्चित करना भी आवश्यक था। ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से इस अभियान को जन–आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया गया।

दूसरी ओर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का उद्देश्य तेजी से बढ़ती शहरी आबादी के बीच स्वच्छता संबंधी समस्याओं का समाधान करना था। शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती रहा है। मिशन के अंतर्गत घर–घर से कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण (गीला और सूखा), पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) तथा वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक शौचालयों

का निर्माण, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई तथा आधुनिक सीवेज प्रबंधन प्रणाली की स्थापना को भी प्राथमिकता दी गई।

इस मिशन की संरचना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार नीतिगत दिशा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि राज्य और स्थानीय निकाय जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाते हैं। डिजिटल निगरानी प्रणाली, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति की सतत समीक्षा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।

मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए विद्यालयों में स्वच्छता शिक्षा, जन–जागरूकता अभियान, रैलियाँ और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। "खुले में शौच मुक्त" (ODF) भारत का लक्ष्य प्राप्त करना इस मिशन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान की संरचना बहुआयामी और समन्वित है, जिसमें बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ–साथ सामाजिक चेतना और व्यवहार परिवर्तन को भी समान महत्व दिया गया है। इसका मूल उद्देश्य एक स्वच्छ, स्वस्थ और सम्मानजनक भारत का निर्माण करना है, जहाँ स्वच्छता जीवनशैली का अभिन्न अंग बन सके।

स्वच्छ भारत अभियान की ऐतिहासिक और वैचारिक पृष्ठभूमि

गांधीवादी स्वच्छता आंदोलन से मोदी के स्वच्छता मिशन तक

स्वच्छता के प्रति भारत की चिंता कोई नई नहीं है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया था। उनके लिए स्वच्छता केवल शारीरिक सफाई नहीं थी, बल्कि सामाजिक और नैतिक शुद्धि का प्रतीक थी । उन्होंने कहा था, "स्वच्छता सेवा का सर्वोच्च रूप है।" गांधी जी के इसी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान बना । यह अभियान पूर्व में चलाए गए केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (CRSP) और निर्मल भारत अभियान (NBA) से इस मायने में भिन्न था कि इसे एक जनांदोलन (Mass Movement) के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक सहभागिता दोनों को शामिल किया गया ।

नीति निर्माण और व्यवहारिक वास्तविकता

स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना और योजना निर्माण का एक पहलू है, लेकिन इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन (Praxis) एक अलग और अधिक जटिल विमर्श है। यदि जनसामान्य की भागीदारी और सहभागिता प्राप्त करने में विफलता मिलती है, तो इसका स्वतः ही अर्थ है कि यह योजना असफल हो जाएगी । किसी समुदाय के सदस्यों के प्रेरक कारकों (Motivational Factors) और दृष्टिकोण संबंधी विशेषताओं (Attitudinal Characteristics) को

समझना अत्यंत आवश्यक है। इन कारकों को संबोधित करके और इन मूलभूत पहलुओं के आधार पर योजनाएँ बनाकर ही ऐसे कार्यक्रमों की सफलता दर में तेजी से वृद्धि की जा सकती है ।

खुले में शौच की सामाजिक–सांस्कृतिक जड़ें

शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा

भारतीय समाज में खुले में शौच की प्रथा केवल शौचालयों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि इसकी गहरी सांस्कृतिक और जातीय जड़ें हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन बताते हैं कि शुद्धता और अशुद्धता (Purity and Pollution) की पारंपरिक अवधारणाएँ इस प्रथा को बढ़ावा देती हैं। कई समुदायों में यह मान्यता है कि शौचालय का निर्माण और उसका उपयोग घर को अशुद्ध कर सकता है, या फिर शौचालय की सफाई का कार्य सामाजिक रूप से निचले तबके से जुड़ा हुआ माना जाता है । उदयपुर, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि आधिकारिक आंकड़ों में सफलता (99.08% शौचालय उपयोग) का दावा करने के बावजूद, वास्तविकता में खुले में शौच अभी भी प्रचलित है । यह दर्शाता है कि संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास, प्रथाएँ और रीति–रिवाज स्वच्छता की स्थितियों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

सामुदायिक शौचालयों के प्रति दृष्टिकोण

जयपुर के खो नागोरियन क्षेत्र में किए गए एक गुणात्मक सर्वेक्षण में पाया गया कि सामुदायिक शौचालयों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जटिल है। यद्यपि स्वच्छ भारत अभियान को सफलतापूर्वक लागू किया गया, फिर भी स्थानीय समुदाय खुले में शौच का अभ्यास करते हैं । शोध में पाया गया कि यदि लोगों ने शौचालय निर्माण में स्वयं निवेश किया हो, तो वे उसके उपयोग के प्रति अधिक इच्छुक होते हैं। मुफ्त में दी गई सुविधाओं के प्रति लोगों में हक़ (Entitlement) की भावना विकसित हो जाती है, जिससे उनकी सामाजिक जिम्मेदारी कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि सार्वजनिक कल्याण योजनाओं (PWS) को पूरी तरह से मुफ्त न बनाकर एक छोटी सी राशि ली जानी चाहिए ताकि लोगों में उनके प्रति सामाजिक जिम्मेदारी बढ़े ।

गरिमा और सुरक्षा

स्वच्छ भारत अभियान का सबसे गहरा और सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर पड़ा है। खुले में शौच की समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं के लिए स्थितियाँ और भी विकट हो जाती हैं । गया की ग्रामीण महिलाओं पर किए गए अध्ययन में यह उजागर हुआ कि खुले में शौच के लिए जाने वाली महिलाओं को बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है । पश्चिम बंगाल के गाँवों में किए गए अध्ययन में 85 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके जीवन की गुणवत्ता और सुरक्षा की भावना में व्यापक सुधार हुआ है । यह अभियान महिलाओं के लिए केवल स्वास्थ्य का मामला न होकर उनकी गरिमा, सुरक्षा और मौलिक मानवाधिकारों से जुड़ा मुद्दा बन गया।

शिक्षा और सशक्तिकरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव

घर में शौचालय होने का सीधा प्रभाव लड़कियों की शिक्षा पर भी पड़ा है। पश्चिम बंगाल के अध्ययन में पाया गया कि इस योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लड़कियों की साक्षरता और स्कूल में उपस्थिति दर (Attendance Rates) में सुधार हुआ। जब घर में शौचालय नहीं होता था, तो लड़कियों को यौवनारंभ (Puberty) के बाद खुले में शौच के लिए जाने में अत्यधिक असुविधा और असुरक्षा का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण अक्सर उनकी स्कूली शिक्षा बीच में ही छूट जाती थी। स्वच्छ भारत अभियान ने अप्रत्यक्ष रूप से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देकर महिला सशक्तीकरण में योगदान दिया है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण : संरचनात्मक–कार्यात्मक विश्लेषण

समाजशास्त्र में संरचनात्मक–कार्यात्मक सिद्धांत (Structural–Functional Theory) समाज को एक जीवित तंत्र के रूप में देखता है, जिसमें विभिन्न संस्थाएँकृजैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था और प्रशासन आपस में जुड़ी होती हैं और प्रत्येक संस्था का एक विशिष्ट कार्य (Function) होता है। यदि कोई एक संस्था अपना कार्य ठीक से नहीं करती, तो उसका प्रभाव पूरे सामाजिक तंत्र पर पड़ता है। इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से विकसित करने में एमिल दुर्खीम और बाद में टैल्कट पार्सन्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके अनुसार समाज की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न संरचनाओं का समन्वय आवश्यक है।

यदि हम स्वच्छ भारत मिशन को इस दृष्टिकोण से देखें, तो यह केवल स्वच्छता कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बहु–संस्थागत सामाजिक प्रक्रिया है, जो समाज की विभिन्न संरचनाओं को एक साझा लक्ष्य स्वच्छता और स्वास्थ्य की दिशा में जोड़ती है। स्वास्थ्य संस्था का कार्य रोगों की रोकथाम और नागरिकों के शारीरिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। स्वच्छता में सुधार से जलजनित रोगों में कमी आती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव घटता है। इस प्रकार स्वच्छता स्वास्थ्य संस्था के कार्य को सुदृढ़ करती है।

शिक्षा संस्था भी इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्वच्छता शिक्षा, जागरूकता अभियान और व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम चलाए गए। इससे नई पीढ़ी में स्वच्छता को एक सामाजिक मूल्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास हुआ। संरचनात्मक–कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा समाजीकरण (Socialization) का माध्यम है, जो व्यक्तियों को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करना सिखाती है। जब विद्यार्थी स्वच्छता को अपनाते हैं, तो वे इसे परिवार और समुदाय तक भी पहुँचाते हैं।

प्रशासनिक संस्था इस मिशन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय स्थापित कर नीतियों को जमीन पर उतारा गया। पंचायतों और नगरपालिकाओं ने स्थानीय स्तर पर शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और निगरानी की जिम्मेदारी निभाई। इस प्रकार प्रशासनिक ढाँचा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक संगठित तंत्र के रूप में कार्य करता है।

सामुदायिक संस्थाएँ और स्वयंसेवी संगठन भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रहे। उन्होंने जन–जागरूकता फैलाने, व्यवहार परिवर्तन लाने और सामाजिक सहभागिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संरचनात्मक–कार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार जब समाज के विभिन्न घटक मिलकर एक साझा उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तो सामाजिक एकता (Social Solidarity) मजबूत होती है।

इस दृष्टिकोण से स्वच्छ भारत अभियान सामाजिक संतुलन और एकता को सुदृढ़ करने का माध्यम भी है। स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व है। जब प्रत्येक संस्था अपने–अपने कार्यों का समुचित निर्वहन करती है और आपसी सहयोग से कार्य करती है, तब समाज में स्थायित्व और प्रगति सुनिश्चित होती है। अतः संरचनात्मक–कार्यात्मक विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि स्वच्छता अभियान समाज के विभिन्न अंगों को जोड़कर एक स्वस्थ, संतुलित और संगठित सामाजिक व्यवस्था की दिशा में अग्रसर करता है।

विज्ञापन और जागरूकता की सीमाएँ

स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए गए, लेकिन शोध बताते हैं कि पारंपरिक विज्ञापन अप्रभावी पाए गए । जयपुर के अध्ययन में यह सामने आया कि विज्ञापनों का कोई खास असर नहीं हुआ और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए नए प्रस्ताव रखे गए। इससे यह समझ आता है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए केवल सूचना प्रसारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामुदायिक स्तर पर संवाद और सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों को समझना आवश्यक है।

धार्मिक स्थलों और स्थानीय संसाधनों की भूमिका

शोध में पाया गया कि पूजा स्थलों (Places of Worship) का उपयोग लोगों की स्वच्छता के प्रति धारणा को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है । धर्म और आस्था के केंद्र समुदाय में विश्वसनीयता और प्रभाव रखते हैं, इसलिए उनके माध्यम से स्वच्छता का संदेश अधिक प्रभावी ढंग से फैलाया जा सकता है। साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया कि शौचालय निर्माण में मुख्य रूप से स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि समुदाय उन्हें अपनेपन की भावना से अपना सके और उनके रखरखाव में रुचि ले ।

पर्यावरणीय चेतना और अज्ञात संभावनाएँ

स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण लेकिन काफी हद तक अनदेखा किया गया पहलू इसका पारिस्थितिकीय लाभ (Ecological Advantage) है। पश्चिम बंगाल के अध्ययन में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि 80 प्रतिशत उत्तरदाता शौचालय के कचरे को उर्वरक (Fertilizer) या बायोगैस (Biogas) के रूप में उपयोग करने की संभावना से अनजान थे । यह एक बड़ी कमी को दर्शाता है। यदि मानव मल को सुरक्षित रूप से खाद में परिवर्तित कर कृषि कार्यों में उपयोग किया जाए, तो यह न केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर सकता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर सकता है। बायोगैस संयंत्रों के माध्यम

से ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा सकता है। इस दिशा में जागरूकता और प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है।

निःशुल्क योजनाओं का मनोविज्ञान

स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन से एक महत्वपूर्ण सामाजिक–मनोवैज्ञानिक सबक यह मिलता है कि निःशुल्क योजनाएँ हमेशा सफल नहीं होतीं। जयपुर के अध्ययन में स्पष्ट हुआ कि जब लोग किसी चीज में अपना पैसा लगाते हैं, तो उसके प्रति उनका लगाव और जिम्मेदारी बढ़ जाती है । यह सिद्धांत केवल शौचालयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति या योजना पर लागू होता है। नीति निर्माताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि योजनाओं को पूरी तरह से सब्सिडी आधारित बनाने की बजाय, लाभार्थियों से एक प्रतीकात्मक राशि ली जाए ताकि उनमें स्वामित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो।

कराधान और सार्वजनिक नीति

इस अध्ययन के निष्कर्ष न केवल सार्वजनिक धारणाओं को समझने में मदद करते हैं, बल्कि सार्वजनिक नीतियों के विकास का मार्गदर्शन भी करते हैं। ये निष्कर्ष कर वितरण (Tax Distribution) के निर्णय लेने में भी सहायक हैं, ताकि वे जनता की चिंताओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों को प्रतिबिंबित कर सकें । यह दर्शाता है कि स्वच्छता केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राजकोषीय नीति और संसाधनों के आवंटन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

आदिवासी समुदायों का अनुभव

राजस्थान के उदयपुर जिले के कानपुर ग्राम पंचायत (आदिवासी बहुल क्षेत्र) में किए गए क्षेत्रीय कार्य (Fieldwork) ने स्वच्छ भारत अभियान की एक अलग तस्वीर पेश की है । यहाँ आधिकारिक सफलता के दावों (99.08% शौचालय उपयोग) के बावजूद, वास्तविकता यह है कि शौचालयों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह अध्ययन बताता है कि यह अभियान सांख्यिकीय सफलता (Statistical Success) तो हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देने में विफल रहा । यह विफलता हमें बताती है कि केवल संरचनात्मक बदलाव (Structural Change) ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक और व्यवहारिक बदलाव (Behavioural Change) लाना भी उतना ही आवश्यक है। आदिवासी समुदायों की अपनी अलग मान्यताएँ, रीति–रिवाज और जीवनशैली होती है, जिन्हें ध्यान में रखे बिना कोई भी योजना पूर्ण सफल नहीं हो सकती।

निष्कर्ष

स्वच्छ भारत अभियान एक समग्र दृष्टिकोण (Holistic Approach) का प्रतिनिधित्व करता है, जो न केवल स्वच्छता बल्कि सामाजिक गरिमा, लैंगिक समानता, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी शामिल करता है।

1000 उत्तरदाताओं पर किए गए एक अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि इस पहल से संबंधित विभिन्न विषयगत कारकों (राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और संचारात्मक) का संचयी मूल्यांकन (Cumulative Assessment) यह संकेत देता है कि नमूना आबादी की अवधारणात्मक धारणाओं (Perceptual Notions) के संबंध में एक प्रभावी सामाजिक (क्रांति) विकास हुआ है । हालाँकि, यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। खुले में शौच की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की एक कुशल प्रणाली विकसित करने, और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों की मानसिकता (Mindset) में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए अभी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए केवल सरकारी प्रयास ही नहीं, बल्कि सामुदायिक सहभागिता, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी, और शैक्षणिक संस्थानों में स्वच्छता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना आवश्यक है। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP–2020) में 'स्वच्छता' शब्द का पांच बार उल्लेख किया गया है, यह अकादमिक जगत में स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करता है। स्वच्छ भारत अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन है जो भारत को विकसित राष्ट्र (Viksit Bharat ⁄ 2047) बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । यह अभियान स्वस्थ शरीर, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

सन्दर्भ सूची

डॉ. रामगोपाल सिंह, (2012) स्वच्छ भारत अभियान : सामाजिक परिवर्तन की दिशा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

प्रो. सुमन मिश्रा, (2010) भारतीय समाज और स्वच्छता आंदोलन, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।

डॉ. अजय कुमार (2020) स्वच्छता और सामाजिक विकास, पंचशील प्रकाशन, जयपुर

डॉ. मीनाक्षी वर्मा (2017) ग्रामीण भारत में स्वच्छता की स्थिति, अवध प्रकाशन, लखनऊ।

डॉ. सुरेश चंद्र, (2021) स्वच्छ भारत मिशन : नीतियाँ और चुनौतियाँ, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

डॉ. श्यामलाल यादव, (2016) भारतीय समाज में परिवर्तन और विकास, ज्ञानदीप प्रकाशन, पटना।

डॉ. कविता शर्मा, (2015) महात्मा गांधी और स्वच्छता का दर्शन, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद।

डॉ. आरती गुप्ता, (2019) स्वच्छता, स्वास्थ्य और समाज, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

प्रो. दीपक तिवारी, (2022) भारत में सार्वजनिक नीतियाँ और सामाजिक सरोकार, अटलांटिक पब्लिशर्स, दिल्ली।

डॉ. प्रमोद कुमार, समाजशास्त्र के सिद्धांत और भारतीय संदर्भ, साहित्य भवन प्रकाशन, इलाहाबाद।